/लोक सभा/

पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा विंग)
भारत सरकार
****

'हर काम देश के नाम'

नई दिल्ली, माघ 13, 1945
शुक्रवार, फरवरी 02, 2023

भारतीय सेना में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल किया जाना

भारतीय सेना का देश भर के पीस स्टेशनों में सीमित संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों)ईवी (को चरणबद्ध तरीके से शामिल करने का विचार है। नवीनतम प्रौद्योगिकीय प्रगति को अपनाने ,हरित ऊर्जा पर जोर देने एवं जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने का लक्ष्य एवं उद्देश्य है। भारतीय सेना पीस स्टेशनों पर निम्नलिखित इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल कर रही है :-

(i) हल्के वाहन)इलेक्ट्रिक(
(ii(बसें)इलेक्ट्रिक(
(iii) मोटरसाइकिलें)इलेक्ट्रिक (।

आज लोकसभा में यह जानकारी रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने श्री मद्दीला गुरूमूर्ति और श्री कुरूवा गोरांतला माधव के प्रश्नों के लिखित उत्तर में दी।

एबीबी/एसएस

/लोक सभा/

pib.nic.in
mod.nic.in

पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा विंग)
भारत सरकार
****

'हर काम देश के नाम'

नई दिल्ली, माघ 13, 1945
शुक्रवार, फरवरी 02, 2023

रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र

सरकार ने देश के रक्षा परिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए कई कार्य योजनाएं बनाई हैं । सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के भारतीय उद्योग की रक्षा अर्जन प्रक्रिया के 2020 – (डीएपी)अध्याय-III में निर्धारित की गई 'मेक प्रक्रिया' के तहत रक्षा प्रणालियों के अभिकल्पन विकास तथा ,विनिर्माण में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाता है , जिसमें प्रोटोटाइप विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान भी शामिल है । पूर्वनिर्धारित वित्तीय और गुणवता प्रत्यायक वाले फर्मों को ग्रीन चैनल दर्जा प्रदान करने के लिए रक्षा स्टोर्स व कलपूर्जों की अधिप्राप्ति के लिए ग्रीन चैनल योजना शुरू की गई है। ग्रीन चैनल प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर प्रेषण पूर्व जांच और रक्षा मंत्रालय के अधीन विभिन्न अधिप्राप्ति अभिकरणों द्वारा की गई संविदाओं के लिए आपूर्तिकर्ता की गारंटी /वारन्टी के तहत स्टोर्स की स्वीकृति से छूट मिल जाती है । दो रक्षा औद्योगिक गलियारों (डीआईसीएस): उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा (यूपीडीआईसी) और तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारा (टीएनडीआईसी) की स्थापना की गई है, जिनका उद्देश्य देश में रक्षा उद्योगों के लिए निवेश आकर्षित करना, घरेलू आपूर्ति श्रृंखला का विकास करना और रक्षा विनिर्माण परिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है । घरेलू रक्षा और ऐरोस्पेस विनिर्माण को बढावा देने के लिए रक्षा परीक्षण अवसंरचना स्कीम शुरू की गई है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य देश में रक्षा परीक्षण अवसंरचना में कमियों को दूर करते हुए एवं सूक्ष्म(एमएसएमई) लघु तथा मध्यम उद्यमों , की भागीदारी पर विशेष ध्यान देकर स्वदेशी रक्षा उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु सरकारी सहायता से सामान्य परीक्षण सुविधा के तौर पर हरित ग्रीनफील्ड रक्षा परीक्षण अवसंरचना स्थापित करना है । रक्षा और ऐयरोस्पेसअनुसंधान एवं विकास संस्थानों तथा शिक्षा जगत में नवाचार और प्रौद्योगिकी ,

विकास को बढ़ावा देने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के उद्देश्य से रक्षा प्रौद्योगिकियों का विकास करने और उनसे संबंधित ,और ऐयरोस्पेस में नवाचार करने समस्याओं का समाधान करने हेतु स्टार्टअप्स तथा एमएसएमई को शामिल करने तथा उन्हें अनुदान वित्त पोषण एवं अनुसंधान एवं विकास जिसके भारतीय रक्षा और ऐयरोस्पेस / करने हेतु अन्य सहायता ,संबंधी जरूरतों के लिए भविष्य में अपनाए जाने की संभावना है प्रदान करने के लिए रक्षा उत्कृष्टता हेतु नवाचार की शुरूआत की गई है। सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों का विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लिए विभिन्न उत्कृष्टता केंद्रों /शैक्षिक संस्थानों जैसे कि आईआईटी, आईआईएससी, आईआईएम आदि के साथ गठजोड़ है।

डीआरडीओ ने ऐसी प्रक्रिया निर्धारित की है जिसके द्वारा इसकी विकसित प्रौद्योगिकियों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए लाइसेंसिंग समझौता (एलएटीओटी) करके उद्योगों को स्थानांतरित किया जाता है। डीआरडीओ ने अपने उद्योग भागीदारों (विकास सह-उत्पादन भागीदार(डीसीपीपी) / विकास भागीदार (डीपी) के लिए शून्य टीओटी शुल्क और भारतीय सशस्त्र बलों और सरकारी विभाग को आपूर्ति के लिए शून्य रॉयल्टी के साथ एक नई टीओटी नीति और प्रक्रिया विकसित की है। अब उद्योगों के लिए डीआरडीओ लैब में परीक्षण सुविधाएं खोल दी गई हैं। डीआरडीओ ने प्रौद्योगिकी विकास निधि (टीडीएफ) शुरू की है जो नवीन रक्षा उत्पादों के अभिकल्प विकास के लिए भारतीय उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। जून 2023 में डीआरडीओ ने उद्योग में रक्षा अनुसंधान एंव विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 75 प्राथमिकता वाले प्रौद्योगिकी क्षेत्र/ उत्पाद/प्रणालियां जारी की है जिन्हें डीआरडीओं नहीं करेगा।

नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास और रक्षा और एरोस्पेस से संबंधित समस्या समाधान की आईडेक्स योजना के तहत युवाओं को स्टार्ट-अप के रूप में जोडा गया है । युवा इंजीनियरों को विभिन्न परियोजनाओं जिसमें अनुसंधान और विकास तथा विनिर्माण शामिल हैके लिए , उत्कृष्टता केंद्रों/ शैक्षिक संस्थानों के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों के समझौते के माध्यम से शामिल किया जाता है । डीआरडीओ ने विभिन्न आईआईटी, आईआईएससी, केंद्रीय और राज्य के विश्वविद्यालयों में 15 डीआरडीओ उद्योग शैक्षिक उत्कृष्टता केंद्र (डीआईए-सीओई) स्थापित किए हैं, जिनमें से 06 का संचालन वर्ष 2023 में शुरू हो गया है। डीपीएसयू और निजी क्षेत्र ऐसे प्रशिक्षित युवाओं को नियुक्त कर रहे हैं जो रक्षा क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं की विशेषज्ञता रखते हैं।

आज लोकसभा में यह जानकारी रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने श्री एस. जगतरक्षकन के प्रश्नों के लिखित उत्तर में दी।

एबीबी/एसएस

/लोक सभा/

पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा विंग)
भारत सरकार
****

'हर काम देश के नाम'

नई दिल्ली, माघ 13, 1945
शुक्रवार, फरवरी 02, 2023

रक्षा बलों में महिलाओं की संख्या

सशस्त्र बलों में महिलाओं की भर्ती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार और तीनों सेनाओं द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं जिनका उल्लेख नीचे किया गया है :-

(i) **(1) महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन**

(कक) 12 सशस्त्र बलों एवं सेनाओं में (सेना चिकित्सा कोर, सेना दंत्य चिकित्सा कोर और सेना नर्सिंग सेवा के अलावा) जहां उन्हें कमीशन किया जाता है, महिला अधिकारियों (डब्ल्यूओ) को स्थायी कमीशन प्रदान किया जा रहा है

(कख) महिला अधिकारियों की तैरते विलेटों में जंगी जहाजों तथा भारतीय नौसेना में विशिष्ट नौसेना प्रचालन अधिकारी (एनएओ) के रूप में भी नियुक्ति की जा रही है।

(कग) वर्ष 2015 में भारतीय वायु सेना द्वारा शुरू की गई सभी समाघात भूमिकाओं में महिला अधिकारियों की भर्ती करने के लिए प्रयोगात्मक योजना को एक स्थायी योजना के रूप में वर्ष 2022 में विनियमित किया गया है।

(ii) **राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में महिला कैडेट.**

सशस्त्र सेनाओं ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में महिला अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश आरंभ कर दिया है। महिला कैडेटों के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे बैच ने क्रमशः जुलाई, 2022, जनवरी, 2023, जुलाई, 2023 और जनवरी, 2024 से एनडीए में प्रशिक्षण आरंभ किया है। इसके लिए यह संगठन सभी आवश्यक प्रशासनिक, प्रशिक्षण तथा नीतिगत परिवर्तन कार्यान्वित करने के लिए समावेशी उपाय सुनिश्चित कर रहा है।

(iii) **<u>कमान नियुक्ति.</u>** महिला अधिकारियों को कर्नल (चयनित ग्रेड) रैंक प्रदान के लिए विचार किया जा रहा है और उन्हें कमान में नियुक्तियां दी जा रही हैं । उन अधिकारियों को जो संक्रमण अवधि के दौरान अनिवार्य कैरियर पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर सके, कैरियर उन्नयन में किसी बाधा को दूर करने के लिए कतिपय छूट भी प्रदान की गई है ।

(iv) अग्निवीर के रूप में महिलाओं का प्रवेश भी सभी तीनों सेनाओं में शुरू हो गया है।

आज लोकसभा में यह जानकारी रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने श्री वी.के.श्रीकंदन के प्रश्नों के लिखित उत्तर में दी।

एबीबी/एसएस

/लोक सभा/

"33"
pib.nic.in
mod.nic.in

पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा विंग)
भारत सरकार
****

'हर काम देश के नाम'

नई दिल्ली, माघ 13, 1945
शुक्रवार, फरवरी 02, 2023

समुद्री डाकुओं द्वारा जहाजों का अपहरण

विगत तीन वर्षों के दौरान समुद्री डाकूओं द्वारा गहरे समुद्र में जहाजों के अपहरण की 07 घटनाओं की सूचना मिली है। व्यापारिक पोत – लीला नारफॉक का अपहरण करने की एक घटना है। दिनांक 04/ ,जनवरी 052024 को चालक दल के सदस्य जहाज पर 21 भारतीय सहित 15 – मछुवाही पोत ,सवार थे। इसके अतिरिक्त आईमैन 28 दिनांक)/01/2024) और मछुवाही पोत अल नईमी)29/01/2024जिन पर कोई भा ,घटनाएं हुईं 02 के अपहरण की (रतीय चालक दल का सदस्य सवार नहीं था।

भारतीय नौसेना समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय और क्षेत्रों से बाहर की नौसेनाओं से भारतीय 2008 समुद्री बलों के साथ अग्रसक्रियता पूर्वक कार्य कर रही हैं। वर्ष / नौसेना ने समुद्री डाकूओं द्वारा जहाज अपहरणरोधी गश्त के लिए अदन की खाड़ी और अफ्रीका के पूर्वी तट में टुकड़ियां तैनात की हैं। कुल से अधिक समुद्री यात्रियों का 25000 पोतों और 3440 सुरक्षित मार्गरक्षण किया गया है। श्रेत्र में समुद्री सुरक्षा को पुनः स्थापित करने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा मध्य अरबसागर और सोमालिया के पूर्वी तट से लगते हुए पोतों की बढ़ी हुई उपस्थिति दूरस्थ पाइलटयुक्त वायुयान द्वारा हवाई निगरानी की जा रही है। / समुद्री गश्तीपोत , निकटवर्ती क्षेत्र में चल रहे व्यापारिक पोतों पर सवार भारतीय / अरब सागर और अदन की खाड़ी चालक दल संबंधी जानकारी के लिए डीजी के साथ प्रभावी संपर्क एवं समन्वय (पोत परिवहन) और सहयोगपूर्ण ढंग से शीघ्र प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा एजेंसियों के भारतीय नौसेना द्वारा क्षेत्र में ,प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त-साथ भी सूचना का आदान समुद्री सुरक्षा को बनाए रखने के लिए उन क्षेत्रों में संचालित मछुवाही पोतों डाऊ की जांच भी की / जा रही है।

भारतीय नौसेना क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बहाल करने के लिए पोतों की तैनातीमध्य अरब , सागर और सोमालिया के पूर्वी तट से लगते हुए क्षेत्र में समुद्री नि◌िगरानी वायुयानदूरवर्ती / पाइलटयुक्त वायुयान द्वारा हवाई निगरानी बढ़ा दी है। पाक जलडमरूमध्य में जलदस्युता की घटना नहीं होने की सूचना प्राप्त हुई है।

आज लोकसभा में यह जानकारी रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने श्री ए. गणेशमूर्ति के प्रश्नों के लिखित उत्तर में दी।

एबीबी/एसएस

/लोक सभा/

पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा विंग)
भारत सरकार
****

'हर काम देश के नाम'

नई दिल्ली, माघ 13, 1945
शुक्रवार, फरवरी 02, 2023

समुद्री सुरक्षा

भारतीय नौसेना की टुकड़ियों की समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए हिन्द महासागर क्षेत्र)आईओआर (में हमारे हित के क्षेत्रों में अभियान आधारित परिनियोजन में नियमित रूप से तैनाती की जाती है। इसके अतिरिक्त ,भारतीय नौसेना की टुकड़ियां समुद्री अधिकार क्षेत्र में जागरूकता में वृद्धि के लिए निगरानी करती हैं और उत्पन्न हो सकने वाली आकस्मिकताओं का समाधान करती हैं। वर्ष 2008से भारतीय नौसेना ने जलदस्युता गश्त के लिए अदन की खाड़ी और अफ्रीका के पूर्वी तट पर टुकड़ियां तैनात की है। कुल 3440 पोतों और 25000 से अधिक समुद्री यात्रियों का सुरक्षित मार्गरक्षण किया है।

भारतीय नौसेना हिन्द महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय और क्षेत्र से बाहर की नौसेनाओं/समुद्री बलों के साथ अग्रसक्रियतापूर्वक सम्पर्क में है। भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा में वृद्धि करने और गैर-पारंपरिक खतरों का एक संगठित और सहयोगात्मक ढंग से सामना करने के लिए मित्र राष्ट्रों के साथ द्विपक्षीय/बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास ,संयुक्त ईईजेड निगरानी ,समन्वित गश्तें)सीओआरपीएटी (की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा के सुदृढ़ीककरण हेतु सूचना मिलन केन्द्र –हिन्द महासागर क्षेत्र)आईएफसी-आईओआर (की स्थापना की है ,जिसका समुद्री सुरक्षा में वृद्धि के लिए वास्तविक समय में सूचना आदान-प्रदान के लिए 25साझेदार राष्ट्रों और 40से अधिक अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय संगठनों के साथ अनुबंध है। इसके अतिरिक्त ,क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा की वर्तमान स्थिति के कारण भारतीय नौसेना की टुकड़ियों की जिबूती से लगी/अदन की खाड़ी, सोमालिया के पूर्वी तट से लगे/उत्तरी/मध्य अरब सागर में व्यापारिक जलयानों की सुरक्षा/यदि आवश्यक हो ,तो सहायता प्रदान करने के लिए तैनाती की जा रही है। इसके अलावा ,आक्रमणों/घटनाओं में लिप्त स्रोतों/कारणों/व्यक्तियों की पहचान करने के लिए मित्र राष्ट्रों के साथ सूचना आदान-प्रदान/आसूचना भी साझा की जा रही है।

आज लोकसभा में यह जानकारी रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल के प्रश्नों के लिखित उत्तर में दी।

एबीबी/एसएस